RNI No. MPHIN/2015/64451 डाक पंजीयन क्र. MP/IDC/1525/2016-2018 IPT indianplasttimes@gmail.com

INDIAN PLAST TIMES

■ INDORE ■ 11 TO 17 JANUARY 2017 ■ प्रति बुधवार ■ वर्ष 02 ■ अंक 20 ■ पृष्ठ 8 ■ कीमत 5 रु.

Inside News

रेलवे की नई पॉलिसी, होगी 16500 करोड़ रुपए की आमदनी

Page 3

बजाज डोमिनर400 की डिलिवरी हुई शुरु, 22 शहरों में मिलेगी

Page 4

इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज उद्घाटन, 22 घंटे तक होगी ट्रेडिंग

Page 7

editoria!

ब्रैंड वाली ट्रेन

सुरेश प्रभु के रेल मंत्रालय संभालने के बाद से इस विभाग में आइडिया की आंधी सी चल रही है। हर तीसरे दिन कोई नया आइडिया नमूदार हो रहा है और उसे मीडिया कवरेज भी भरपूर मिल रही है। मुश्किल सिर्फ एक है कि ये सारे आइडिया मिलकर भारतीय रेलवे की दशा में रत्ती भर भी सुधार नहीं कर पा रहे। और तो और, रेल दुर्घटनाओं की संख्या बढ़ती जा रही है और नामी-गिरामी ट्रेनों की भी पहचान दस-बीस घंटे लेट होने से लेकर ऐन मौके पर कैंसिल हो जाने तक के लिए बनती जा रही है। रेल मंत्री का लेटेस्ट आइडिया ट्रेनों और स्टेशनों को बोली लगाकर बड़े औद्योगिक घरानों को विज्ञापन के लिए सौंप देने का है। इससे भारतीय रेलवे को कुछ आमदनी जरूर हो सकती है, लेकिन जब-तब कुछ हास्यास्पद स्थितियां भी पैदा हो सकती हैं। किसी कॉफी के नाम पर चलने वाली ट्रेन आपको किसी कोल्ड ड्रिंक के नाम पर चल रहे स्टेशन पर पहुंचाएगी। विज्ञापन के मामले में सबसे ज्यादा सक्रियता शराब कंपनियां दिखाती हैं- अपने ब्रैंड नाम से बिकने वाले पानी को आगे रखकर। काफी संभावना है कि एक-दो साल बाद आप किसी व्हिस्की के नाम वाली ट्रेन में सपरिवार यात्रा करते नजर आएं। स्टेशन पर घोषणा हो रही होगी कि शराब के अमुक ब्रैंड वाली एक्सप्रेस अगले पांच मिनट में पहुंचने वाली है। ऐसे में स्टेशन का नाम अगर किसी मसालेदार चिप्स के ब्रैंड वाला हुआ, तब तो मजा ही आ जाएगा। इसका कमजोर पहलू यह है कि ट्रेन और स्टेशनों की सुरक्षा व्यवस्था का ध्यान रखने वालों को अपनी ड्यूटी ज्यादा चुस्ती से निभानी होगी, क्योंकि पैसे देने वाली कंपनियां रेलवे की अपनी कलर स्कीम (जिसमें लाल-हरे सिग्नल भी शामिल हैं) की परवाह किए बगैर स्टेशनों का चप्पा-चप्पा चमकीले रंगों से भर डालेंगी। ये सारी मुश्किलें बर्दाश्त की जा सकती हैं, बशर्ते भारतीय रेलवे अपनी सेफ्टी-सिक्युरिटी, टाइमिंग और क्वालिटी पर पर्याप्त ध्यान दे। अभी तो हाल यह है कि लोगों को अपनी छोटी-छोटी जरूरतों के लिए भी रेल मंत्री के ट्विटर हैंडल को टैग करना पड़ रहा है। इसके बावजूद इनके पूरा होने का प्रतिशत बहुत कम है। दरअसल यह विभाग अपने मंत्री से गुमनामी में रहकर मशक्कत करने की मांग करता है, लेकिन इसका दुर्भाग्य कि खबरों के भूखे मंत्री ही लगातार इसके हिस्से आ रहे हैं।

सऊदी अरब ने चला नया दांव

महंगा पेट्रोल-डीजल भरवाने के लिए हो जाइए तैयार

नई दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

भारत के अंदर सस्ता पेट्रोल और डीजल पाने के दिन जल्द ही जाने वाले हैं और महंगे दिन आने वाले हैं। क्योंकि भारत को कच्चा तेल निर्यात करने वाले देशों ने अपनी आपूर्ति घटाने का फैसला किया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ओपेक देशों ने भारत और अमेरिका को होने वाली कच्चे तेल की सप्लाई को कम करने का फैसला किया है। ओपेक देशों के सदस्य सऊदी अरब और इराक ने इस बावत फैसला करते हुए गुरुवार को इसकी प्रक्रिया शुरु कर दी है। भारत सऊदी अरब और इराक से करीब 40 फीसदी कच्चे तेल का आयात करता है। ओपेक देशों के बीच कच्चे तेल का उत्पादन घटाने को लेकर पहले ही सहमति बन चुकी है। वहीं सऊदी अरब ने एशिया और अमेरिका को कच्चे तेल के निर्यात पर दिए जाने वाले डिस्काउंट को खत्म करते हुए कच्चे तेल के प्रीमियम को बढ़ा दिया है। टीओआई की खबर के मुताबिक आने वाले दिनों में सऊदी अरब 7 फीसदी तक अपनी कच्चे तेल की आपूर्ति को कम कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ भारत को दूसरे सबसे बड़े तेल निर्यातक देश इराक ने भी कच्चे तेल का उत्पादन घटाने का फैसला किया है। ओपेक देशों के बीच नवंबर, 2016 में कच्चे तेल का उत्पादन घटाने को लेकर सहमति बनी थी। ओपेक देशों ने तय किया था कि कच्चे तेल का उत्पादन 18 लाख बैरल प्रति दिन घटाने पर सहमति बनी है। एक बैरल में 159 लीटर कच्चा तेल होता है। वहीं भारत करीब रोजाना 19 लाख बैरल कच्चे तेल का आयात करता है। इस खबर को भारत जैसे देशों के लिए खराब माना जा सकता है क्योंकि अभी भी भारत जैसे कच्चे तेल के लिए दूसरे देशों पर ही निर्भर हैं। आपको बताते चले कि वर्ष 2014 में जहां कच्चे तेल की 112 डॉलर प्रति बैरल थी जोकि गिरकर 40 डॉलर प्रति बैरल के नीचे चली गई थी। ओपेक देशों में समझौता होने के बाद कच्चे तेल की कीमत फिर तेज हुई है और आज 54 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर पहुंच चुकी है। कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में यह कीमत बढ़कर 60 डॉलर प्रति बैरल के ऊपर पहुंच जाएगी। इससे सरकार पर दबाव बढ़ सकता है और ऑयल मॉर्केटिंग कंपनियों को तेल की कीमतों में बढ़ोतरी करनी पड़ सकती है। इसके अलावा सरकार कच्चे तेल की कीमत कम करने के लिए एक्साइज ड्यूटी में कटौती करनी पड़ सकती है।

कच्चे तेल का भाव 50 डॉलर तक आया

API रिपोर्ट में बढ़ा स्टॉक, OPEC की उत्पादन कटौती पर भी आशंका

विदेशी बाजार में कच्चे तेल के बाजार को लेकर अधिकतर फंडामेंटल भाव पर दबाव रहने की ओर इशारा कर रहे हैं जिस वजह से विदेशई बाजार में कच्चे तेल का भाव घटकर 50.80 डॉलर प्रति बैरल तक आ गया है, मंगलवार को भाव ने 50.71 डॉलर प्रति बैरल का निचला स्तर छुआ था जो करीब 6 हफ्ते में सबसे कम भाव है। विदेशी बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में आई नरमी की वजह से मंगलवार को घरेलू बाजार में भी गिरावट देखने को मिली है और कमोडिटी एक्सचेंज एमसीएक्स पर कच्चा तेल 65 रुपये घटकर 3,509 रुपे प्रति बैरल के स्तर पर बंद हुआ है।

कच्चे तेल की कीमतों में आई गिरावट के पीछे अमेरिका में स्टॉक में हुई बढ़ोतरी को माना जा रहा है, अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टिट्यूट की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले हफ्ते अमेरिका में कच्चे तेल के स्टॉक में करीब 15 लाख बैरल की बढ़ोतरी हुई है। स्टॉक को लेकर अमेरिकी ऊर्जा विभाग की रिपोर्ट आज शाम को जारी होगी।

कच्चे तेल के उत्पादन में कटौती को लेकर और गैर देशों में जो फैसला हुआ था उसके ठीक तरह से लागू होने के लेकर भी बाजार में आशंका है जिस वजह से भी भाव में गिरावट आई है। वहीं दूसरी ओर ऐसे देशों ने अपना उत्पादन बढ़ा दिया है जो इस फैसले में शामिल नहीं थे, ऐसे में कच्चे तेल की सप्लाई में कमी आने की संभावना कम ही लग रही है। इधर अमेरिकी करेंसी डॉलर में फिर से हल्की रिकवरी आई है जिस वजह से भी कच्चे तेल के बाजार पर दबाव आया है, डॉलर इंडेक्स रिकवर होकर 102.16 तक पहुंच गया है, डॉलर में तेजी आने पर कमोडिटीज पर दबाव रहता है।

नोटबंदी: 25,000 करोड़ रुपए का नकदी लेनदेन डिजिटल हुआ

नई दिल्ली। एक सर्वे के अनुसार नोटबंदी के बाद 25000 करोड़ रुपए का नकदी आधारित लेनदेन डिजिटल हो गया है यानि इस तरह का लेनदेन अब डिजिटल माध्यमों से हुआ। भारतीय स्टेट बैंक के आर्थिक अनुसंधान विभाग ने 30 दिसंबर 2016 से तीन जनवरी 2017 के दौरान अपने सर्वेक्षण के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला है। इसके अनुसार 15 प्रतिशत लेनदेन अब एम वालेट व प्वाइंट आफ सेल मशीनों जैसे इलेक्ट्रोनिक भुगतान तौर तरीकों के जरिए हो रहे हैं। एसबीआई रिसर्च ने रिपोर्ट में कहा है,' इसका मतलब यह है कि बीते दो महीने में नकदी आधारित 25,000 करोड़ रुपए का लेनदेन अब डिजिटली हो रहा है। अगर ऐसा है तो यह अच्छी शुरआत है।'

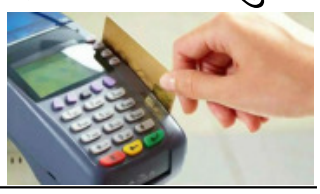

कच्चे तेल पर निर्भरता कम करने के लिए मनोरंजन इंडस्ट्री को मजबूत करने में जुटा सऊदी अरब

रियाद। एजेंसी

जस्टिन बीबर के सॉन्ग 'लेट मी लव यू' पर वीकंड में क्लबों में थिरकते लोग आपको दुनिया में किसी भी देश में देखने को मिल जाएंगे। परंपरागत रूप से इस्लामिक रूढ़ीवादी देश सऊदी अरब के लिए यह नया है। डांस, ओपेरा और माइम डांस करती हुई महिलाएं नहीं नजर आएंगी, लेकिन पुरुष और बच्चे आपको स्टेज पर परफॉर्म करते दिखेंगे। रियाद की एक यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले मोहम्मद अल-मावला ने कहा, 'यह नया अनुभव है।' किंग अब्दुल्लाह इकॉनमिक सिटी में आयोजित इस कार्यक्रम को लेकर मावला ने कहा कि हम पसंद करेंगे कि किंगडम में इस तरह के शो का आयोजन होता रहे।

ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब सरकार ने देश की लगातार बिगड़ती इकॉनमी को सुधारने के लिए फन इंडस्ट्री को मजबूत करने का फैसला लिया है ताकि इसके जरिए राजस्व जुटाया जा सके। इसके चलते ही अल्ट्रा-कंजर्वेटिव समाज में म्यूजिक

और मनोरंजन से जुड़े प्रतिबंधों को ढीला किया जा रहा है ताकि इसके जरिए ही कुछ रकम जुटाई जा सके। मनोरंजन को लेकर सऊदी किंगडम हमेशा से सख्त रहा है। यहां तक कि म्यूजिक भी धीमी आवाज में ही बजाने की अनुमति दी जाती है। अब तक लोग दुबई और बहरीन यात्रा करने पर ही कोई मूवी या शो देख पाते थे। लेकिन, अब सऊदी सरकार ने लोगों के फन को ही एक इंडस्ट्री के तौर पर तब्दील करने का फैसला लिया है।

टिकट बेचने की वेबसाइट चलाने वाले सऊदी नागरिक अनमार फाथलदीन का कहना है कि इससे उनकी कमाई में इजाफा होगा। हालांकि वह यह उम्मीद नहीं करते कि सऊदी अरब में सब कुछ बदल जाएगा। अनमार कहते हैं कि जब हम ट्रैवल पर होते हैं तो नॉर्मल जिंदगी जीते हैं। उन्होंने कहा, 'विदेश जाने पर मेरी पत्नी बेपर्दा होकर साथ में घूम सकती है। हम लाइव म्यूजिक इवेंट्स में जा सकते हैं और बच्चों के साथ बीच पर जा सकते हैं। लेकिन, यहां ऐसा कभी नहीं होने वाला।'

विजन 2030 का हिस्सा हैं ये बदलाव

सऊदी किंग के बेटे और डेप्युटी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने 2030 का जो इकॉनमिक विजन तैयार किया है, यह सब उसका हिस्सा है। इस नीति के तहत सऊदी अरब तेल पर अपनी आर्थिक निर्भरता कम करते हुए नए उद्योगों का विस्तार करने की रणनीति पर चल रहा है। सऊदी प्रिंस ने नई आर्थिक नीति के तहत सरकारी सब्सिडी पर लगाम कसने और महिलाओं को भी वर्कफोर्स का हिस्सा बनाने जैसे कई प्रयोग शुरू करने पर विचार किया है।

2020 तक होंगे 450 क्लब

कच्चे तेल पर निर्भरता कम करते हुए अन्य उद्योगों के विस्तार में मनोरंजन भी अहम सेक्टर है। डेप्युटी क्राउन प्रिंस के ब्लू प्रिंट के मुताबिक 2020 तक देश में 450 से ज्यादा क्लब खोले जाने की योजना है, जिनमें तमाम तरह की कल्चरल ऐक्टिविटीज और इवेंट्स होंगे। सऊदी सरकार ने देश में प्रति व्यक्ति मनोरंजन व्यय को 6 पर्सेंट तक बढ़ाने का फैसला लिया है।

कच्चा तेलः अमेरिका सहित इराक और ईरान में उत्पादन बढ़ने की उम्मीद से भाव पर दबाव

कच्चे तेल की कीमतों को काबू में करने के लिए सऊदी अरब और रूस की अगुवाई में भले ही कुछ देश उत्पादन कटौती कर रहे हैं लेकिन इन देशों के अलावा ध्फिं संगठन में जिन देशों को उत्पादन बढ़ाने की छूट मिली हुई है वह लगातार उत्पादन बढ़ा रहे हैं साथ में भाव लंबे समय से 50 डॉलर के ऊपर है जिस वजह से अमेरिका में भी उत्पादन बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है।

शायद यही वजह है कि उत्पादन कटौती की डील के बावजूद विदेशी बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट देखी जा रही है, नायमेक्स पर कच्चे तेल का भाव घटकर 52 डॉलर प्रति बैरल तक आ गया है, सोमवार को भाव ने 51.76 प्रति बैरल का निचला स्तर छुआ था। बीते कारोबारी सत्र के दौरान कमोडिटी एक्सचेंज पर कच्चा तेल 108 रुपये घटकर 3,574 रुपये प्रति बैरल के स्तर पर बंद हुआ है।

संगठन में सऊदी अरब के बाद दूसरे बड़े उत्पादक देश इराक ने अपने ऑयल कंपनियों को उत्पादन बढ़ाने की हिदायत दी है, इराक के अलावा ईरान भी उत्पादन को बढ़ा रहा है और अमेरिका में ऑयल रिग्स में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है जिस वजह से वहां पर भी उत्पादन बढ़ रहा है।

फरवरी आखिर तक हालात सामान्य होंगे: SBI प्रमुख

अहमदाबाद। भारतीय स्टेट बैंक (एस.बी.आई.) की चेयरमैन अरुंधति भट्टाचार्य ने आज कहा कि नोटबंदी से पैदा हुए मौजूदा हालात फरवरी के आखिर तक सामान्य हो जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने अर्थव्यवस्था के डिजिटलीकरण पर जोर दिया। यहां वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट में भाग लेने पहुंची भट्टाचार्य ने हवाई अड्डे पर संवाददाताओं से कहा, 'हमारा मानना है कि (नोटबंदी से उपजे) हालात फरवरी के आखिर तक सामान्य हो जाएंगे।' उन्होंने कहा कि एस.बी.आई. अपनी शाखाओं में पर्याप्त नकदी उपलब्ध कराकर यह सुनिश्चित करना चाहता है कि खाताधारकों को कोई दिक्कत नहीं हो। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम में वह डिजिटललीकरण के प्रोत्साहन पर चर्चा करने की कोशिश करेंगी।

ऑयल मार्केटिंग कंपनियों से ज्यादा डिविडेंड की मांग

नई दिल्ली। सरकार ने ऑयल मार्केटिंग कंपनियों से डिविडेंड की रकम दोगुनी करने की मांग की है। पिछले साल इन कंपनियों ने 8 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा का डिविडेंड दिया था। बता दें कि आईओसी ने वित्त वर्ष 2013 में 6.2 रुपए प्रति शेयर, वित्त वर्ष 2014 में 8.7 रुपए प्रति शेयर, 2015 में 6.6 रुपए प्रति शेयर और 2016 में 14 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड दिया था।

एचपीसीएल ने वित्त वर्ष 2013 में 8.5 रुपए प्रति शेयर, वित्त वर्ष 2014 में 15.5 रुपए प्रति शेयर, 2015 में 24.5 रुपए प्रति शेयर और 2016 में 34.5 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड दिया था। बीपीसीएल ने वित्त वर्ष 2013 में 11 रुपए प्रति शेयर, वित्त वर्ष 2014 में 17 रुपए प्रति शेयर, 2015 में 22.5 रुपए प्रति शेयर और 2016 में 31 रुपए प्रति शेयर डिविडेंड दिया था।

आईओसी, एचपीसीएल और बीपीसीएल ने वित्त वर्ष 2016 में डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन सहित सरकार को कुल 8118 करोड़ रुपए डिविडेंड का भुगतान किया जिसमें आईओसी की हिस्सेदारी 4079 करोड़ रुपए, एचपीसीएल की हिस्सेदारी 1406 करोड़ रुपए और बीपीसीएल की हिस्सेदारी 2633 करोड़ रुपए रही।

वित्त वर्ष 2016 में आईओसी के पास नकदी के तौर पर 2013.65 करोड़ रुपए, एचपीसीएल के पास 2799.35 करोड़ रुपए और बीपीसीएल के पास 4629 करोड़ रुपए थे। वित्त वर्ष 2017 की पहली छमाही में बीपीसीएल का मुनाफा 16 फीसदी बढ़कर 3926 करोड़ रुपए रहा है। वित्त वर्ष 2016 की पहली छमाही में बीपीसीएल का मुनाफा 3395 करोड़ रुपए रहा था।

एचपीसीएल की बात करें तो वित्त वर्ष 2017 की पहली छमाही में एचपीसीएल का मुनाफा 125 फीसदी बढ़कर 2780 करोड़ रुपए रहा है। वित्त वर्ष 2016 की पहली छमाही में एचपीसीएल का मुनाफा 1236 करोड़ रुपए रहा था। जबकि अगर आईओसी की बात करें तो वित्त वर्ष 2017 की पहली छमाही में आईओसी का मुनाफा 85 फीसदी बढ़कर 11391 करोड़ रुपए रहा है। वित्त वर्ष 2016 की पहली छमाही में आईओसी का मुनाफा 6141करोड़ रुपए रहा था।

भारतीय मानक ब्यूरो ने बदले हॉलमार्किंग मानक

अब तीन ग्रेड में ही मिलेगा सोना

नई दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

भारतीय मानक ब्यूरो ने सोने की हॉलमार्किंग से जुड़े मानक में बदलाव किया है। अब सोने के आभूषण तीन ग्रेड- 14,18 और 22 कैरेट में ही उपलब्ध होंगे। गोल्ड ज्वैलरी पर ही उसका ग्रेड दर्ज होगा। मानक में यह बदलाव एक जनवरी से लागू है। साथ ही सोने के सिक्के एवं बार (बिस्किट) पर हॉलमार्क की सील लगाने का लायसेंस केवल रिफायनरी को ही दिया जाएगा। भारतीय मानक ब्यूरो ने स्वर्ण आभूषण हॉलमार्किंग संबंधी मानकों को पुनरीक्षित (रिवाइज) कर दिया है। नए साल में अब हॉलमार्किंग वाली ज्वैलरी तीन ग्रेड में ही बेची जाएगी। इससे पहले तक हॉलमार्किंग वाले स्वर्ण आभूषण 10 अलग-अलग ग्रेड में बेचे जा रहे थे। इतने प्रकार की शुद्धता वाले आभूषण को लेकर उपभोक्ता भ्रमित होता था।

ज्वैलरी पर इस तरह रहेगी मुहर मानक ब्यूरो के उपनिदेशक जनसंपर्क ने एक अधिकृत जानकारी में बताया है कि 22 कैरेट अर्थात एक ग्राम सोने में 916 मिलीग्राम शुद्धता, 18 कैरेट यानि 750 मिलीग्राम शुद्धता एवं 14 कैरेट से आशय है 1000 मिलीग्राम सोने में 585 मिलीग्राम शुद्धता। आभूषण जितने कैरेट सोने का होगा उस पर उतने अंक के साथ अंगरेजी का 'के' अक्षर की मुहर रहेगी। मसलन 22 कैरेट के लिए '22 के916' की सील एवं ज्वैलर की पहचान मुहर भी रहेगी। रिफायनरीज को मिलेगा लायसेंस सोने के सिक्के एवं बार (बिस्किट) के बारे में हॉलमार्क लायसेंस केवल सोने का शोधन करने वाली रिफाइनरीज को ही दिया जाएगा। सिक्के आदि के लिए ज्वैलर्स को हॉलमार्किंग का लायसेंस नहीं दिया जाएगा। एक किलोग्राम सोने के बिस्किट को सोने के कारोबार में 'बार' अथवा कैडबरी के नाम से बुलाया जाता है।

रेलवे की नई पॉलिसी

होगी 16500 करोड़ रुपए की आमदनी

नई दिल्ली। एजेंसी

रेलवे अपनी आय बढ़ाने के लिए नए-नए रास्ते तलाशने की कोशिश कर रही है। रेलवे ने माल भाड़ा और यात्री किराए के आलावा आमदनी के दूसरे स्त्रोत पर केंद्रित करना शुरू करना कर दिया है। इसके लिए रेलवे ने गैर किराया राजस्व के लिए अपनी नई पॉलिसी तैयार की है। नई नीति के तहत रेलवे ने अनुमान लगाया है कि वह सालाना 16,500 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आमदनी कर सकती है।

क्या है ये नई पॉलिसी

बता दें कि रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने राजधानी दिल्ली में रेलवे की गैर किराया राजस्व पॉलिसी को हरी झंडी दिखा दी है। इस नई रेल किराया राजस्व पॉलिसी के तहत देशभर में चलने वाली सभी ट्रेनों को विनायल रैपिंग एडवरटाइजिंग के लिए ई-नीलामी करके बेचा जाने वाला है। इस पॉलिसी के तहत ट्रेनों को 10 साल के लिए नीलाम किया जाएगा। इसके तहत देशभर में चलने वाली 10,000 से ज्यादा यात्री ट्रेनों को विज्ञापन के लिए नीलाम किया जाएगा। देशभर में चलने वाली सभी ट्रेनों को इसके लिए 6 श्रेणियों में बांटा गया है।

नीलामी के लिए तय की गई हैं ये 6 श्रेणियां:

1. राजधानी, शताब्दी, जन शताब्दी और डबल डेकर 2. सुपर फास्ट, एसी सुपरफास्ट, स्पेशल और मेल एक्सप्रेस ट्रेनें 3. ईएमयू, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई 4. डीएमयू और एमईएमयू ट्रेनें 5. गरीब रथ 6. अन्य ट्रेनें

नीलामी की कीमत अलग-अलग

ऊपर बताई गई सभी 6 प्रकार की कैटेगरी के लिए नीलामी की बेसिक कीमत अलग-अलग रखी गई है। रेलवे की पीएसयू राइट्स को कंसल्टेंट के तौर पर नियुक्त किया गया है। राइट्स ने अर्नस्ट एंड यंग को प्रोफेशनल मीडिया मार्केटिंग इवैल्यूशन एजेंसी यानि पीएमएमईए नियुक्त किया है। राइट्स और पीएमएमईए मिलकर पूरी की पूरी नीलामी प्रक्रिया को मैनेज करेंगे।

ऐसे लगाए जाएंगे विज्ञापन

रेलवे के मुताबिक हर ट्रेन के लिए संबंधित कंपनी हर कोच के अंदर तकरीबन 250 स्क्वायर फीट का विज्ञापन लगा सकेगा। डिब्बे के अंदर की जगहों को पहले से ही रेलवे निर्धारित करके बताएगा। विनायल रैपिंग एयर कंडीशन कोच की खिड़कियों पर भी की जाएगी। बशर्ते खिड़कियों के जरिए 70 फिसदी विजिबिलिटी संभव हो सके। नॉन एसी कोच की खिड़कियों पर विनायल रैपिंग की अनुमति नहीं होगी। ट्रेन ब्रांडिंग के जरिए रेलवे हर साल तकरीबन 2000 करोड़ रुपये कमाने का इरादा रखती है।

आउट ऑफ होम एडवरटाइजिंग पॉलिसी

रेलवे ने आउट ऑफ होम एडवरटाइजिंग पॉलिसी भी बनाई है। इस पॉलिसी के तहत देशभर के सभी रेलवे स्टेशनों को डिजिटल एडवरटाइजिंग से जोड़ा जाएगा। बड़ी-बड़ी वीडियो स्क्रीन लगाई जाएंगी। जिनपर रेलवे की सूचनाओं के अलावा अलग-अलग तरीके के विज्ञापन चलाए जाएंगे। इन विज्ञापनों के जरिए रेलवे ने हर साल 6000 करोड़ रुपए से ज्यादा की आमदनी होने का अनुमान लगाया है।

स्टेशन पर लगेगी डिजिटल स्क्रीन

स्टेशनों पर बड़ी-बड़ी डिजिटल स्क्रीन लगाने के साथ ही रेलवे का इरादा सभी ट्रेनों के अंदर डिजिटल स्क्रीन लगाने का है। इन स्क्रीन पर कंटेंट ऑन डिमांड चलाया जाएगा। इसी के साथ रेलवे रेल रेडियो लाने का भी प्लॉन बना रही है। इस तरह की डिजिटल क्रांति से भारतीय रेलवे तकरीबन 6000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आमदनी करने का अनुमान लगा रहा है।

ATM भी लगेंगे स्टेशन पर

रेलवे ने अपने सभी स्टेशनों पर बैंकों के एटीएम लगाने का फैसला भी किया है। अपनी नई नीति के तहत रेलवे अब बैंकों को 10 साल के लिए एटीएम स्पेस उपलब्ध कराएगा। एटीएम के लिए दी जाने वाली जगहों के किराए का निर्धारण ई-नीलामी के जरिए किया जाएगा। नई एटीएम पॉलिसी से भारतीय रेलवे को ढाई हजार करोड़ की अतिरिक्त आमदनी होने का अनुमान है।

सुरेश प्रभु ने नया आईआरसीटीसी रेल कनेक्ट ऐप लॉन्च किया

जानें इसकी खासियतें

नई दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने और रेल टिकट पाने में आसानी के लिए रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने मंगलवार को नया यात्री मोबाइल ऐप 'आईआरसीटीसी रेल कनेक्ट' लॉन्च किया। इस मौके पर प्रभु ने कहा, 'वर्तमान में ई-टिकटिंग प्रणाली से रोजाना 10 लाख से ज्यादा टिकट बुक हो रहे हैं जोकि कुल बुकिंग का 58 फीसदी है। इसे बढ़ावा देने के लिए और यूजर्स की आसानी के लिए एक नया एंड्रायड आधारित मोबाइल एप्लिकेशन 'आईआरसीटीसी रेल कनेक्ट' विकसित किया गया है।' उन्होंने कहा, 'रेल कनेक्ट को अगली पीढ़ी की टिकटिंग प्रणाली के रूप में विकसित किया गया है जो उच्च प्रदर्शन क्षमता और उच्च सुरक्षा से लैस है।' नया ऐप पहले से ज्यादा सुरक्षित है और इसमें पिन आधारित लॉग इन प्रणाली है, जिसमें बार-बार यूजरनेम और पासवर्ड डालने की जरूरत नहीं होती। मंत्री ने कहा कि नया ऐप आईआरसीटीसी की ई-वॉलेट के साथ काम करेगा, ताकि तेजी से और आसानी से भुगतान हो सके। प्रभु ने बताया, 'नए ऐप में 40 से ज्यादा बैंकों से नेट बैंकिंग, डेबिट-क्रेडिट कार्ड, पेटीएम, पेयू, मोबिक्विक आदि से भुगतान की सुविधा है।'

GST और नोटबंदी से मजबूत होगी अर्थव्यवस्था, इस साल दिखेगा असर- वित्तमंत्री

गांधीनगर। एजेंसी

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने वाइब्रेंट गुजरात में नोटबंदी का गुणगान किया है। जेटली ने कहा कि अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए बड़े फैसलों की जरूरत है। हर बड़े फैसले को लागू करने में कठिनाई होती है। वित्त मंत्री ने जीएसटी पर कहा कि अधिकतर मुद्दों का समाधान किया जा चुका है। कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे बचे हैं. मुझे आशा है कि अगले कुछ हफ्तों में हल निकल जाएगा। एक देश एक टैक्स सिस्टम से अर्थव्यवस्था बड़ी और साफ होगी।

नोटबंदी पर जेटली ने कहा कि नोटबंदी के प्रारंभिक प्रभावों के बाद इससे जीडीपी अधिक स्वच्छ और ज्यादा बड़ी होगी। कागजी नोटों के बहुत ज्यादा होने की अपनी बुराइयां हैं और यह अपने प्रति लोभ जगाती है। जेटली ने कहा कि यह महत्वपूर्ण है कि जीएसटी सितंबर, 2016 से पहले लागू किया जाना चाहिए, लेकिन हम इसे अप्रैल तक लागू करना चाहते हैं। जीएसटी और नोटबंदी से आर्थिक वृद्धि को बल मिलेगा, असर इस साल दिखेगा। जेटली ने कहा कि केंद्र में 2014 में आए परिवर्तन कि वजह से भारत विकास कि ओर आगे बढा है। सरकार ने काफी बड़े फैसले लिए हैं। वाइब्रेंट गुजरात पर जेटली ने कहा कि यह सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक सम्मेलन बन गया है, जो भारत और गुजरात दोनों की अर्थव्यवस्था के लिए बड़ी बात है।

अपने बिजनेस का कराएं रजिस्ट्रेशन मिलेंगे कई फायदे

यह है तरीका

नई दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

केंद्र सरकार की ओर से लिए गए नोटबंदी के फैसले के बाद अब व्यापारी वर्ग यह समाधान तलाशने में जुटा है कि किस तरह से बिना रजिस्ट्रेशन वाले बिजनेस का रजिस्ट्रेशन कराया जाए ताकि वह आयकर विभाग एवं राजस्व विभाग की ओर से होने वाली किसी भी कार्रवाई से बच सके और रजिस्टर्ड बिजनेस के फायदों को उठा सके।

ई-मुंशी (ईमुंशी डॉट कॉम) के टैक्स एक्सपर्ट अंकित गुप्ता ने एक आम व्यापारी से जुड़ी इसी समस्या का हल देने की कोशिश की है और यह बताने की कोशिश की है कि आयकर और वैट अधिनियम के अंतर्गत निर्दिष्ट नियमों को पालन कर कैसे आप अपनी राह आसान बना सकते हैं। जानिए कितनी आसानी से आप अपने बिजनेस को रजिस्टर्ड करवा सकते हैं और उसके फायदे उठा सकते हैं।

1. एक रजिस्टर्ड व्यापारी के रूप में काम करने के लाभ

- ई वाणिज्य व्यवसाय की तरह वैश्विक मंच पर अपने व्यापार को बढ़ाने के अधिक अवसर
- उधार लेने के अधिक विकल्पों की उपलब्धता हैं, विशेष रूप से एमएसएमई रजिस्ट्रेंट के लिए (लघु और मध्यम पैमाने के कारोबार पर)
- निर्यात बढ़ाने के अवसर यहां होते हैं लेकिन इंपोर्ट-एक्सपोर्ट कोड लेने की जरूरत
- राजस्व प्राधिकरण के दंड और अभियोजन पक्ष की कार्यवाही से राहत।
- अपने अनन्य व्यापार को पेटेंट करवाएं

2. अपने बिजनेस को कहां रजिस्टर्ड करवाएं

- बहुत सारे बिजनेसमैन और सर्विस प्रोवाइडर इस तथ्य से अनजान होते हैं कि वो सरकार को मामूली शुल्क भुगतान कर अपने बिजनेस को रजिस्टर्ड (पंजीकृत) करवा सकते हैं।
- आप चाहे ट्रेडर हो या होलसेलर या एक्सपोर्टर या फिर सामान की खरीद या बिक्री में संलग्न कोई भी व्यक्ति आपको अपने राज्य के वैट अधिनियम के तहत अपने बिजनेस को रजिस्टर करवाने की जरूरत होती है।
- समझिए अगर आप दिल्ली में बिजनेस कर रहे हैं तो आप मात्र 1025 रुपए के भुगतान पर अपने बिजनेस को रजिस्टर्ड करवा सकते हैं।
- अगर आप सर्विस प्रोवाइडर हैं तो आप बिना किसी शुल्क भुगतान के सेंट्रल बोर्ड और उत्पाद एवं सीमा शुल्क (सीबीईसी) की साइट www.aces.gov.in पर जाकर अपना बिजनेस रजिस्टर्ड करवा सकते हैं।
- अगर आप एक मैन्युफैक्चरर हैं, उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं के निर्माण करते हैं और आपका लेन-देन 90 लाख रुपए से अधिक है तो आप केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) में रजिस्ट्रेशन करवाना होगा।
- अगर आप वस्तुओं और सेवाओं के निर्यातक के रूप में अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आपको विदेश व्यापार महानिदेशक कार्यालय से इंपोर्ट-एक्सपोर्ट कोड लेने की जरूरत होगी।

3. कौन करवा सकता है रजिस्ट्रेशन

- केंद्र सरकार और किसी भी राज्य सरकार से रजिस्ट्रेशन प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को न ही कंपनी का गठन करने की जरूरत होती है और न ही फर्म को बनाने की व्यक्ति अपने नाम पर मालिकाना हक के तौर पर रजिस्ट्रेशन प्राप्त कर सकता है।
- रजिस्ट्रेशन करवाने वाले व्यक्ति को एक फोटो, पेन, आधार, बैंक अकाउंट डिटेल और एड्रेस प्रूफ देना पड़ता है।
- वहीं अगर काफी सारे लोग एक बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो वो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप का गठन कर रजिस्ट्रेशन प्राप्त कर सकते हैं। कारपोरेट मामलों के मंत्रालय के माध्यम से ऐसा किया जा सकता है।
- एक इनकॉरपोरेशन का खर्च उससे जुड़े पार्टनर्स की संख्या और पूंजी पर निर्भर करता है, जिस भी कंपनी का रजिस्ट्रेशन वो करवाना चाहते हैं।

बजाज डोमिनर400 की डिलिवरी हुई शुरु, 22 शहरों में मिलेगी

नई दिल्ली । आईपीटी नेटवर्क

बजाज ऑटो ने अपनी हाल ही लॉन्च हुई पॉवरफुल बाइक डोमिनर-400 की डिलिवरी शुरू कर दी। यह बाइक बजाज ऑटो ने 22 शहरों में स्थित डीलरों के माध्यम से ग्राहकों को मिलेगी। बजाज ऑटो ने नई डोमिनर-400 पिछले साल 15 दिसम्बर को भारत में लॉन्च किया था। मार्किट में इस बाइक अच्छा रिस्पोंस मिल रहा है और इसकी ऑनलाइन बुकिंग भी शुरु है।

डोमिनर 400 की कीमत

नई बजाज डोमिनर400 की दिल्ली में एक्स-शो रूम कीमत 1.30 लाख रुपये रखी गई है। जबकि इसके ABS वर्जन की कीमत 1.50लाख रुपए रखी है।

डोमिनर 400 की इंजन डिटेल्स

इंजन की बात करें तो बाइक में बाइक में 373cc का सिंगल सिलिंडर DTS-i इंजन लगा है। जो 34.5bhp की पावर और 35Nm टार्क देता है। इसमें 6-स्पीड गियर बॉक्स दिया गया है। यह बाइक 8.32 सेकेंड में 0 से 100 किमी की स्पीड तक पहुंच जाती है। बाइक की टॉप स्पीड 148 kmph है।

डोमिनर 400 के अन्य फीचर्स

नई डोमिनर 400 में साइज़ की बात करें तो इसकी लम्बाई 2156mm, ऊंचाई 813mm, चौड़ाई 1112mm है जबकि इसका व्हीलबेस 1453mm है। बाइक का ग्राउंडक्लेरेंस 157mm है तो वही इसका वजन 182mm है। इतना ही नहीं बाइक में 13 लीटर का फ्यूल टैंक लगाया है। डिज़ाइन के मामले में नई dominor एक पॉवरपैक्ड मशीन नज़र आती है। बेतर रोशिनी के लिए इसमें फुल LED ऑटो हेडलैंप दिया गया है।

डोमिनर 400 है बजाज की सबसे पॉवरफुल बाइक

यह बाइक बजाज की अब तक की सबसे पावरफुल मशीन है।लुक्स आउट डिज़ाइन के मामले में नई डोमिनर 400 प्रीमियम और स्पोर्टी बाइक है। युथ को लुभाने के लिए इसमें कई खूबियों को शामिल किया गया है। बाइक में ABS तकनीक को शामिल किया गया है। इसके फ्रंट में 320mm और रियर में 230mm डिस्क ब्रेक लगे है। बाइक 3 कलर्स में है। यह बाइक फ्यूल इंजेक्शन तकनीक से लैस है।

ईपीएफ सदस्यों-पेंशनरों के लिए आधार कार्ड हुआ अनिवार्य

नई दिल्ली। एजेंसी

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने अपने 50 लाख पेंशनभोगियों और करीब 4 करोड़ अंशधारकों के लिए इस महीने यानी जनवरी के आखिर तक आधार संख्या उपलब्ध कराना अनिवार्य कर दिया है. जिन अंशधारकों या पेंशनभोगियों के पास आधार नहीं है, उन्हें महीने के आखिर तक सबूत देना होगा कि उन्होंने इसके लिए आवेदन कर दिया है. कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस), 1995 के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए पेंशनरों और इसके मौजूदा सदस्यों के लिए आधार कार्ड प्रस्तुत करना अब अनिवार्य कर दिया गया है. इसके अलावा ईपीएफओ ने 'माफी योजना' चालू की है जिसके तहत फर्में एक रुपये के जुर्माने के साथ कर्मचारियों के नाम ईपीएफओ में रजिस्टर करवा सकेंगी.

श्रम मंत्रालय ने जारी किया नोटिफिकेशन

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने अपने करीब चार करोड़ सदस्यों और 50 लाख पेंशनरों के लिए आधार नंबर अनिवार्य कर दिया है. सदस्यों और पेंशनरों को एक महीने के भीतर आधार नंबर देना होगा या फिर आधार के लिए आवेदन करने का प्रमाण देना होगा. जिन अंशधारकों या पेंशनभोगियों के पास आधार नहीं है, उन्हें माह के अंत तक यह सबूत देना होगा कि उन्होंने इसके लिये आवेदन कर दिया है. हालांकि इसका फायदा वो लोग भी उठा पाएंगे जिन्होंने खुद को आधार कार्ड के लिए एनरोल्ड तो करा दिया है लेकिन उन्हें अभी आधार कार्ड मिला नहीं है, वो अपनी आधार आईडी दिखाकर ऐसा कर सकते हैं.

अगर आप चाहते हैं कि आपको संगठन की ओर से सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ मिलता रहे तो यह जरूर करवा लें.

इसके अलावा वो सदस्य और पेंशनर जिन्होंने अभी तक खुद को आधार नंबर के लिए एनरोल्ड नहीं कराया है, उन्हें हर हाल में 31 जनवरी 2017 से पहले अपने नजदीकी एनरोलमेंट सेंटर जाकर खुद को एनरोल्ड करवाना होगा. किसी सूरत में अगर अगर आपके आस-पास एनरोलमेंट सेंटर नहीं है तो ईपीएफओ के लिए यह जरूरी है कि वो उक्त स्थान पर एनरोलमेंट फैसिलिटी उपलब्ध करवाए. ईपीएफओ के केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त वीपी जॉय ने कहा कि फिलहाल पेंशनभोगियों के साथ-साथ अंशधारकों को आधार या पंजीकरण प्रति 31 जनवरी, 2017 तक उपलब्ध कराना होगा. यह ईपीएफओ द्वारा उपलब्ध सेवाएं हासिल करने के लिए जरूरी है.' जॉय ने कहा, 'हम माह के अंत में स्थिति की समीक्षा करेंगे और अंशधारकों और पेंशनभोगियों को 12 अंकों वाला आधार संख्या देने के लिए कुछ और समय दे सकते हैं.'

ईपीएफओ ने पूरे देश में सभी 120 फील्ड ऑफिसों को इस अभियान का प्रचार करने का निर्देश दिया ताकि सेवायोजकों के बीच जागरूकता लाई जा सके. हर महीने केंद्र सरकार सभी सदस्यों के पेंशन खाते में 1.16 फीसद अंशदान देती है जबकि 8.33 फीसद अंशदान सदस्यों को करना होता है.

बिना पैनिक बटन वाले मोबाइल फोनों का 28 फरवरी के बाद भारत में आयात नहीं

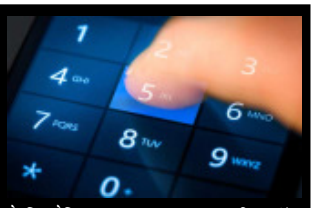

नई दिल्ली। दूरसंचार विभाग ने बिना पैनिक बटन (आपातकालीन कॉल बटन) वाले मोबाइल फोन 28 फरवरी 2017 तक आयात करने की अनुमति दे दी है। पहले 'सभी फोनों में पैनिक बटन और जीपीएस सुविधा नियम-2016' के तहत बिना ये सुविधा वाले फोनों को एक जनवरी तक आयात की अनुमति दी गई थी। विभाग ने कार्यालय ज्ञापन में कहा कि यह निर्णय किया गया है कि पैनिक बटन या आपातकालीन कॉल बटन की सुविधा नहीं रखने वाले मोबाइल फोनों का आयात 28 फरवरी 2017 तक जारी रहेगा. पहले यह तिथि एक जनवरी 2017 थी। सरकार ने पिछले महीने अप्रैल में घोषणा की थी कि 1 जनवरी 2017 से देश में बिकने वाले सभी हैंडसेटों में पैनिक बटन होना अनिवार्य होगा। इस आदेश के अनुसार, पैनिक बटन दबाने पर सीधे इमरजेंसी नंबर 112 पर कॉल हो जाएगी।

नोटबंदी का असरः वाहनों की बिक्री में हुई 16 साल में सबसे बड़ी गिरावट

नई दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

नोटबंदी का असर हर तरफ देखने को मिला और ऑटो इंडस्ट्री भी नोटबंदी के असर से बच नहीं पाई तभी दिसंबर 2016 में वाहनों की बिक्री 18.66 फीसदी घट रह गई। यह पिछले 16 साल में वाहनों की बिक्री में अब तक की सबसे बड़ी मासिक गिरावट है। वही टू-व्हीलर्स मार्किट में दिसम्बर महीने में अब तक की सबसे बड़ी गिरावट देखने को मिली है। वही बीते साल की तुलना में अप्रैल-दिसम्बर 2016 के दौरान टू-व्हीलर्स मार्किट ने 10.04 की बढ़ोतरी दर्ज की है। यह आंकड़े सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (सियाम) की ओर से जारी किये हैं। जबकि घरेलू कार बाज़ार में यात्री वाहनों की बिक्री दिसंबर महीने में 1.36 प्रतिशत घटकर 2,27,824 वाहनों की रही। जबकि पिछले साल समान अवधि में यही आंकड़ा 2,30,959 यात्री वाहन का रहा। घरेलू बाजार में कारों की बिक्री दिसंबर में 8.14 प्रतिशत घटकर 1,58,617 वाहन रही। दिसंबर 2015 में 1,72,671 कारों की बिक्री घरेलू बाजार में हुई थी। अप्रैल से दिसम्बर 2016 के दौरान ऑटो इंडस्ट्री ने कुल 19,236,932 वाहन बेचें। यह बीते वर्ष इसी अवधि की तुलना में 7.31 फीसदी ज्यादा है। इसमें यात्री वाहन, कमर्शियल वाहन, थ्री-व्हीलर्स, टू-व्हीलर्स और क्वैड्रासाइकिल शामिल हैं, जबकि अप्रैल से दिसम्बर 2015 में इंडस्ट्री ने 17,925,959 वाहन बेचें थे। सियाम के अनुसार नोटबंदी का असर लोकल ऑटो इंडस्ट्री पर दिखा है लेकिन नोटबंदी से ऑटो सेल्स पर असर अस्थायी है। इसके अलावा सियाम ने यह भी कहा देश में नोटबंदी का असर शहरी इलाकों के मुकाबले ग्रामीण इलाकों में देखने को मिला है। क्योंकि बाइक्स और छोटी कारों में गिरावट इसका एक प्रमाण है। और अब ऑटो जगत को आने वाले बजट से काफी उम्मीदें रहेंगी।

दुबई में गोल्ड पर 5% इंपोर्ट ड्यूटी से गुलजार होगा इंडियन बाजार!

कोलकाता। एजेंसी

दुबई ने गोल्ड और डायमंड ज्वैलरी पर 5 पर्सेंट की इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी है। इससे इस रीजन में इंडिया से होने वाले एक्सपोर्ट में गिरावट आएगी। डीमॉनेटाइजेशन के बाद से इंडिया में गोल्ड की खरीद-फरोख्त में सुस्ती आई है। दुबई के कदम से एक और चोट लग सकती है। हालांकि अच्छी बात यह है कि लोकल मार्केट में गोल्ड महंगा होने के चलते दुबई शिफ्ट हुई ब्राइडल ज्वैलरी की खरीदारी इंडिया का रुख कर सकती है। इंडिया और दुबई में मिलने वाले गोल्ड की कीमत में सिर्फ 5 पर्सेंट के फर्क के चलते शॉपिंग करने वालों के लिए खाड़ी देश अट्रैक्टिव नहीं रह जाएगा। इंडिया में गोल्ड पर 10 पर्सेंट इंपोर्ट ड्यूटी लगती है। मुंबई की दशकों पुरानी ज्वैलरी फर्म पोपली एंड संस के डायरेक्टर राजीव पोपली ने कहा, 'दुबई में कंज्यूम होनेवाली लगभग 45 से 50 पर्सेंट गोड ज्वैलरी इंडिया से जाती है। इससे दुबई एक्सपोर्ट करनेवाले कुछ बड़े इंडियन ज्वैलर्स को नुकसान होगा।'

गोल्ड ट्रेड के ऑफिशियल्स का कहना है कि दुबई में गोल्ड पर इंपोर्ट ड्यूटी लगने से दुबई में ज्वैलरी डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग को बड़े पैमाने पर बढ़ावा मिलेगा और इंडियन इंपोर्ट पर निर्भरता घटेगी। कुछ बड़े रिटेल चेन पहले से ही ऐसी फैसिलिटी चला रहे हैं। उन पर 5 पर्सेंट इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगी। दुबई में इंपोर्ट ड्यूटी को इंडियन गोल्ड इंडस्ट्री वहां वैल्यू ऐडेड टैक्स व्यवस्था लागू होने के संकेत के तौर पर देख रहा है। दुबई को ज्वैलरी एक्सपोर्ट करनेवाली दिग्गज कंपनी राजेश एक्सपोर्ट्स के चेयरमैन राजेश मेहता कहते हैं, 'हमारी ज्वैलरी आमतौर पर दुबई से दुनिया के कई देशों में रीएक्सपोर्ट की जाती है। रीएक्सपोर्ट के लिए दुबई में इंपोर्ट होनेवाली ज्वैलरी पर कोई ड्यूटी नहीं है। दुबई में लोकल यूज के लिए हम जो गोल्ड ज्वैलरी एक्सपोर्ट करते हैं उस पर 5 पर्सेंट ड्यूटी लगेगी।' इंडिया में हाथ से बनी ज्वैलरी दुबई में मशहूर है। मुंबई के झावेरी बाजार और अहमदाबाद के माणक चौक जैसे मशहूर बाजार दुबई के गोल्ड सूक में डीमॉनेटाइजेशन के बाद इंडियन टूरिस्ट्स की गोल्ड ज्वैलरी डिमांड में तेज गिरावट आई है। गोल्ड सूक में कई जाने माने होलसेल और रिटेल ज्वैलर्स के स्टोर्स हैं। गोल्ड की भरोसेमंद शुद्धता के चलते इंडियन टूरिस्ट्स के लिए दुबई में ज्वैलरी की खरीदारी का अलग आकर्षण है। अगर वहां टूरिस्ट ठीक-ठाक ज्वैलरी खरीदें और उनको पहनकर आएं तो वे उन पर 10 पर्सेंट की कस्टम्स ड्यूटी बचा सकते हैं। ऑल इंडिया जेम एंड ज्वैलरी ट्रेड एसोसिएशन के डायरेक्टर अशोक मीनावाला कहते हैं, 'पिछले कई वर्षों में एक खास वर्ग की तरफ से होनेवाली ब्राइडल ज्वैलरी की खरीदारी बड़ा हिस्सा दुबई शिफ्ट हो गया था। इसका बड़ा हिस्सा अब इंडिया लौटेगा।'

दिसंबर में कार बिक्री 8.14 प्रतिशत, यात्री वाहन बिक्री 1.36 प्रतिशत घटी

नयी दिल्ली। एजेंसी

घरेलू बाजार में यात्री वाहनों की बिक्री दिसंबर महीने में 1.36 प्रतिशत घटकर 2,27,824 वाहन रही। एक साल पहले इसी महीने में 2,30,959 यात्री वाहन बेचे गये थे। घरेलू बाजार में कारों की बिक्री दिसंबर में 8.14 प्रतिशत घटकर 1,58,617 वाहन रही। दिसंबर 2015 में 1,72,671 कारों की बिक्री घरेलू बाजार में हुई थी। वाहन विनिर्माताओं के संगठन सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स :सियामः द्वारा जारी आंकड़ों में यह जानकारी दी गई है।

दिसंबर 2016 में मोटरसाइकिलों की बिक्री भी 22.5 प्रतिशत घटकर 5,61,690 इकाई रही जबकि एक साल पहले इसी माह में 7,24,795 मोटरसाइकिलें बेची गईं थी। यदि सभी तरह के दोपहिया वाहनों की बात की जाये तो दिसंबर में इनकी बिक्री 22.04 प्रतिशत घटकर 9,10,235 इकाई रही जबकि एक साल पहले इसी महीने में 11,67,621 दुपहिया वाहनों की बिक्री हुई थी।

दिसंबर में वाणिज्यिक वाहनों की बिक्री भी 5.06 प्रतिशत कम होकर 53,966 इकाई रही। एक साल पहले दिसंबर में 56,840 वाणिज्यिक वाहन बेचे गये थे।

कुल मिलाकर दिसंबर माह में सभी तरह के वाहनों की बिक्री में 18.66 प्रतिशत की कमी आई और यह 12,21,929 रही जबकि दिसंबर 2015 में कुल मिलाकर 15,02,314 वाहन बेचे गये थे।

बजट 2017-18 के लिए वित्त मंत्रालय ने ट्विटर के जरिए सुझाव मांगे, तीन दिन में सब्मिट करें

नई दिल्ली। एजेंसी

अगले महीने की पहली तारीख यानी 1 फरवरी को केंद्रीय बजट पेश किया जाना है। वित्त मंत्रालय ने आगामी बजट को रोजगार उन्मुख बनाने के लिए लोगों से ट्विटर पर सुझाव और टिप्पणियां देने के लिए कहा है। यह प्रयोग अगले तीन दिन तक जारी रहेगा। इस संबंध में मंत्रालय के आधिकारिक ट्विटर खाते पर कहा गया है, '' अधिक रोजगार पैदा करने के लिए सरकार को किस क्षेत्र पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए?'

इसके लिए मंत्रालय ने चयन करने के लिए एमएसएमई, सस्ते मकान, वाहन एवं कलपुर्जे और परिधान क्षेत्र का विकल्प दिया है। मंत्रालय ने इनमें से किसी के चयन और संबंधित क्षेत्र के बारे में सुझाव मांगे हैं।

ट्विटर पर लोग मंत्रालय के आधिकारिक खाते पर इस प्रश्न के विकल्पों का उत्तर दे सकते हैं। फरवरी की पहली तारीख को पेश किए जाने वाले बजट के संबंध में पूछे गए इस प्रश्न पर शुरूआती चुनाव में एमएसएमई क्षेत्र और सस्ते मकान को ज्यादा लोगों ने विकल्प के तौर पर चुना है।

भारत में 2020 तक कार्ड, एटीएम, पीओएस सब बेकार हो जाएंगेः नीति आयोग

बेंगलूरू। एजेंसी।

नोटबंदी के बाद देश में डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के बीच नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत ने आज कहा कि डेबिट और क्रेडिट कार्ड, एटीएम और पांइट ऑफ सेल :पीओएसः मशीनें सभी 2020 तक देश में बेमानी हो जायेंगी।

उन्होंने कहा भारत आज वित्तीय प्रौद्योगिकी और सामाजिक नवोन्मेष दोनों क्षेत्रों में भारी उठापटक के दौर से गुजर रहा है। इन क्षेत्रों में यहां काफी कुछ नई चीजें हो रहीं हैं और यही उठापटक भारत को काफी आगे ले जायेगी।

कांत ने कहा 2020 तक मेरा मानना है कि अगले ढाई साल में भारत में सभी तरह के डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, एटीएम मशीनें और पीओएस मशीनें पूरी तरह से बेकार हो जायेंगी। कांत यहां प्रवासी भारतीयों के सम्मेलन 2017 के एक सत्र को संबोधित कर रहे थे। सम्मेलन तीन दिन तक चलेगा।

उन्होंने कहा, भारत में ये सभी चीजें बेकार हो जायेंगी और भारत यह छलांग लगायेगा कि हर भारतीय यहां केवल अपना अंगूठा लगाकर तीस सैंकिंड में लेनदेन करने लगेगा ..... ।

युवा प्रवासी भारतीय दिवस को संबोधित करते हुये कांत ने कहा, हम इस समय देश में डिजिटल तरीकों से भुगतान को तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं और इसमें कई नये तरीकों के सामने आने से काफी उठापटक चल रही है। उन्होंने कहा कि इस उठापटक के बीच भारत ने बायोमेट्रिक में काफी प्रगति की है जिससे काफी सफलता मिलेगी। उन्होंने हाल में जारी भीम एप और आधार के जरिये होने वाली भुगतान प्रणाली का जिक्र किया। कांत ने कहा कि भारत व्यापक तौर पर नकदी से चलने वाली अर्थव्यवस्था रही है लेकिन अब यहां एक अरब के करीब मोबाइल ग्राहक है और इतने ही बायोमेट्रिक भी हैं। उन्होंने कहा कि भारत को अनौपचारिक से औपचारिक अर्थव्यवस्था बनने की जरूरत है। अब तक यहां केवल दो से ढाई प्रतिशत लोग ही कर का भुगतान करते रहे हैं।

इस्पात मंत्रालय ने कोकिंग कोयला, निकेल पर आयात शुल्क घटाने की मांग की

नयी दिल्ली। इस्पात मंत्रालय ने कोकिंग कोयला तथा निकेल दोनों पर आयात शुल्क में कमी की मांग की है। यह मांग 2017-18 के बजट पेश किये जाने से ठीक पहले की गयी है। ये दोनों उत्पाद इस्पात निर्माण के लिये महत्वपूर्ण है और इससे क्षेत्र को गति मिल सकती है। इस्पात सचिव अरूणा शर्मा ने पीटीआई से विशेष बातचीत में कहा कि निकेल, कोकिंग कोयला तथा गैस के मामले मे आयात पर निर्भरता काफी अधिक है। उन्होंने कहा, हम इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि क्या सीमा शुल्क तथा आयात शुल्क पर गौर करने की जरूरत है। इस पर अभी चर्चा जारी है। देखते हैं बजट में यह कैसे रहता है। सचिव ने कहा कि इस्पात मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय को दी अपनी सिफारिश में कोकिंग कोयला, निकेल एवं गैस पर आयात शुल्क में कमी लाने को कहा है। जहां निकेल पर आयात शुल्क पांच प्रतिशत है, वहीं कोकिंग कोयले के मामले में यह 2.5 प्रतिशत है। उन्होंने कहा कि भविष्य में पैलेट के विनिर्माण में गैस की जरूरत बढ़ेगी और प्रधानमंत्री ने जैसा कि कहा है कि अर्थव्यवस्था गैस आधारित होने जा रही है। पैलेट लौह अयस्क का छोटा बॉल है और इसका उपयोग इस्पात बनाने में किया जाता है। कोकिंग कोयला के आयात में कमी लाने के लिये अरूणा ने कहा कि उनका मंत्रालय वाशरीज में निवेश के लिये कोयला मंत्रालय से बातचीत कर रहा है।

मकर संक्रांति क्या है?

प्रति माह होने वाला सूर्य का निरयण राशि परिवर्तन संक्रांति कहलाता है। सामान्यतया आमजन को सूर्य की मकर संक्रांति का पता है, क्योंकि इस दिन दान-पुण्य किया जाता है। इसी दिन सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण होते हैं। संक्रांति को सजीव माना गया है। प्रति माह संक्रांति अलग-अलग वाहनों व वस्त्र पहन कर, शस्त्र, भोज्य पदार्थ एवं अन्य पदार्थों के साथ आती है। सूर्य का एक राशि से दूसरी राशि में जाने को ही संक्रांति कहते हैं। एक संक्रांति से दूसरी संक्रांति की अवधि ही सौरमास है। वैसे तो सूर्य संक्रांति 12 हैं, लेकिन इनमें से चार संक्रांति महत्वपूर्ण हैं, जिनमें मेष, कर्क, तुला, मकर संक्रांति है। मकर संक्रांति के शुभ मुहूर्त में स्नान, दान व पुण्य का शुभ समय का विशेष महत्व है। मकर संक्रांति के पावन पर्व पर गुड़ व तिल लगाकर नर्मदा में स्नान करना लाभदायी होता है।

भारत के विभिन्न क्षेत्रों में मकर संक्रांति की धूम

मकर संक्रांति पर्व देशभर में हर्षोउल्लास के साथ मनाया जाता है। यह पर्व किसी न किसी रूप में देश के प्रत्येक हिस्से में अपनी छाप छोड़ता दिखाई देता है। मकर संक्रांति पर्व को कई नामों से जाना जाता है कहीं इसे पोंगल तो कहीं लोहडी। तो कहीं उत्तरायण पर्व, नाम चाहे कोई भी हो लेकिन इस पर्व का एक ही अर्थ है और वह है जीवन में प्रकाश और प्रेम का आगमन।

इस उत्सव के आगमन से ही सूर्य उत्तरायण होते हैं यह समय देवताओं का दिन कहा जाता है इस दिन से शुभ कार्यों का आरंभ होता है। मकर संक्रान्ति के दिन से मौसम में बदलाव आना आरम्भ होता है। दिन बड़े होने लगते हैं और रातें छोटी होने लगती हैं। ग्रीष्म ऋतु का प्रारम्भ होता है। मकर संक्रान्ति के दिन खाई जाने वाली वस्तुओं में जी भर कर तिलों का प्रयोग किया जाता है। इस दिन तिल का सेवन और साथ ही दान करना अत्यंत शुभ होता है।

गुजरात में मकर संक्रांति पर्व - गुजरात में मकर संक्रांति का पर्व उत्तरायण पर्व के नाम से अधिक प्रचलित है। इस दिन लोग पतंग उड़ाने में लगे रहते हैं यहां इस उत्सव की रंगत इसी रूप में अधिक देखी जाती है। आकाश में चारों ओर रंग बिरंगी पतंगे उड़ते हुए देखी जा सकती है सभी लोग घरों की छतों पर जाकर इस उत्सव में बढ़-चढ़कर भाग लेते हैं।

बंगाल में मकर संक्रांति उत्सव की धूम - बंगाल में मकर संक्रांति उत्सव के दिन स्नान के पश्चात तिल दान करने का बहुत महत्व होता है। इस संदर्भ में एक कथा भी जुड़ी है कि मकर संक्रान्ति के दिन ही गंगा जी भगीरथ के पीछे-पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम से होते हुए सागर में जा मिली थीं अतः मान्यता अनुसार गंगासागर में स्नान-दान करने हेतु लाखों श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगता है। यहां स्नान करने के पश्चात भक्त लोग दान की परंपरा का निर्वाह करते हैं।

कर्नाटक में मकर संक्रांति- कर्नाटक में मकर संक्रांति का त्यौहार फसल से संबंधित रहा है। इस दिन बैलों और गायों को सजाया जाता है तथा कुछ शोभायात्राओं का आयोजन भी होता है। इस दिन सभी लोग नए वस्त्र पहनते हैं और एक दूसरे को मकर संक्रांति की बधाई देते हुए गले मिलते हैं तथा गन्ना नारियल, दालें इत्यादि अपने पास रखते हैं साथ ही सभी लोग मिलकर पतंग उड़ाने का आनंद लेते हैं। ■

मकर संक्रांति पर लोहड़ी और भांगड़ा की धूम

मकर संक्रांति को हरियाणा और पंजाब में लोहड़ी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन पंजाब में भांगड़ा और गिद्दे की थाप पर थिरकते हुए लोग मस्ती में झूमते हुए दिखाई देते हैं। शाम के समय अंधेरा होते ही एक स्थान पर लकडियों और उपलों का ढेर लगाकर उसकी पूजा करते हुए वहां आग्नि प्रजज्वलित कि जाती है और अग्नि पूजा करते हुए तिल, गुड़ और मक्के के भूने हुए दानों को अग्नि में डाला जाता है तथा साथ ही अग्नि के चारों और परिक्रमा करते हुए पूजा कि जाती है। पूजा पश्चात मूंगफली, तिल की बनी हुई गजक और रेवड़ियाँ को आपस में बांटकर खुशियां मनाते हैं। यह पर्व तब और भी अधिक रंग में रंग जाता है जब किसी के घर में नई बहू का आगमन होता है या बच्चे का जन्म होता है।

लोहड़ी का उत्सव

संस्कृति और उल्लास का पर्व, 13 जनवरी, 2017

पंजाब में जीवन को एक नये अंदाज में जिया जाता है। मौज-मस्ती और जिन्दगी के हर पल को जी भर के जीने की परम्परा यहां देखी जा सकती है। लोहड़ी पर्व मकर संक्रान्ति की पूर्व संध्या में भारत के उत्तरी राज्यों जिसमें हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और अन्य आसपास के राज्यों में मनाया जाता है। इसी दिन यहां की संस्कृति अपने एक अलग रूप में होती है।

लोहड़ी में पंजाब से परिचय - लोहड़ी केवल पंजाब तक ही सीमित नहीं है। पर वहां इस त्यौहार की बात ही कुछ और है। इस दिन यहां रंग और खुशी अपने शबाब पर होती है। पंजाब का नाम आयें, और सरसों का साग, मक्के की रोटी, मिट्टी की खुशबू, घड़े के पानी की सोंधी महक की बात न हों, ऐसा कैसे हो सकता है। लोहड़ी त्यौहार ही है, प्रकृति को धन्यवाद कहने का, फिर उसे पंजाबी अंदाज देना हो, तो कुछ अलग जोश तो होगा है। लोहड़ी को मकर संक्रान्ति के आगमन की दस्तक भी कहा जाता है।

लोहड़ी संगीत संध्या- लोहड़ी की संध्या में लोकगीतों का खूबसूरत समां आलम बांध देता है। मन को मोह लेने वाले गीतों कुछ इस प्रकार के होते हैं कि एक बार को जाता हुआ बैरागी भी अपनी राह भूल जायें। और सबसे अहम भंगड़ा और सोनी कुड़ियों के गिद्धे भला उन्हें कोई भूल सकता है। हिन्दू धर्म में यह मान्यता है कि आग में जो भी समर्पित किया जाता है वह सीधे हमारे देवों-पितरों को जाता है। लोहड़ी के दिन खेतों में झूमती फसलों को घर ला, अग्नि देव प्रजव्लित कर उसके चारों ओर नाच- गाकर शुक्रिया अदा किया जाता है। यह भी देवों की पूजा करने का एक अलग तरीका है। बड़े-बड़े ढोलों की थाप, जिसमें बजाने वाले थक जायें, पर पैरों की थिरकन में कमी न हों, रेवड़ी , मूंगफली का स्वाद सब एक साथ रात भर चलता रहता है।

लोहड़ी का एक विशेष वर्ग - यूं तो लोहड़ी उत्तरी भारत में प्रत्येक वर्ग, हर आयु के जन के लिये खुशियां लेकर आती है। परन्तु युवक-युवतियों और नवविवाहित दम्पत्तियों के लिये यह दिन विशेष होता है। लोहड़ी की संध्यां में जलती लकड़ियों के सामने नवविवाहित जोड़े अपनी वैवाहिक जीवन को सुखमय व शान्ति पूर्ण बनाये रखने की कामना करते हैं।

प्रेरक प्रसंग

स्वर्ग जाने की पात्रता

एक बार एक धनवान ईसा मसीह के पास उनसे मिलने आया। उसे अपने सुखद जीवन में तो कोई कमी नहीं थी, लेकिन वह स्वर्ग जाकर वहां का नजारा देखना चाहता था। उसने ईसा मसीह से निवेदन किया, 'आपने स्वर्ग का द्वार तो खोल ही दिया है। इसलिए अब कृपा कर मुझे भी वहां भिजवा दीजिए। मैं भी वहां जाना चाहता हूं।' ईसा मसीह ने उसकी ओर देखा और पूछा- 'क्या तुम सचमुच स्वर्ग में जाना चाहते हो? क्या तुम्हारी वहां जाने की तैयारी पूरी हो चुकी है? तुमने स्वर्ग जाने की अपनी पात्रता ठीक से परख ली है?'

इस पर धनवान ने उत्तर दिया- 'जी हां, मैं सचमुच स्वर्ग में जाना चाहता हूं और इसके लिए मेरी तैयारी भी पूरी हो चुकी है।' यह सुनकर ईसा ने फिर उससे कहा, 'पहले तुम अच्छी तरह से सोच लो और फिर उत्तर दो।' धनवान ने कहा- 'जी हां, मैंने बहुत सोच समझकर ही उत्तर दिया है। ईसा मसीह बोले- 'जब तुमने सोच ही लिया है और अब तुम्हारी तैयारी भी हो गई है, तो अपनी तिजोरियों की तमाम चाबियां मुझे सौंप दो।' धनवान यह सुनकर अचकचा गया-'मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं भला। अपनी जिंदगी भर की कमाई किसी और को कैसे दे दूं।' ईसा ने उससे कहा, 'तब फिर तुम स्वर्ग नहीं जा सकते। स्वर्ग जाने वाले इंसान में जो गुण होने चाहिए, वे तुममें नजर नहीं आते। तुम्हारी तो रग-रग में लालच समाया हुआ है। तुम जैसे लोगों के लिए स्वर्ग में कोई स्थान नहीं है।' धनवान ने उनसे क्षमा मांगी और तय किया कि वह पहले खुद में स्वर्ग जाने की सलाहियत पैदा करेगा फिर ईसा मसीह से वहां भेजने का निवेदन करेगा।

बेला गर्ग

इंडियन तड़के के साथ ब्रेकफास्ट परोसेगी मैकडॉनल्ड्स

मुंबई। आईपीटी नेटवर्क

मैकडॉनल्ड्स एक ब्रांडेड मेन्यू के साथ ब्रेकफास्ट रिवॉल्यूशन का प्लान बना रही है। उसकी योजना ब्रेकफास्ट मेन्यू में मसाला डोसा बर्गर से लेकर अंडा भुर्जी तक परोसने की है। मैकब्रेकफास्ट को नए व्यंजनों के साथ कंज्यूमर्स को सुबह-सुबह लुभाने के मकसद से पेश किया जाएगा। इनमें से कुछ डिश केवल सुबह के वक्त अवलेबल होंगी। इस इंडस्ट्री में सुस्ती के बीच कंपनी को उम्मीद है कि इससे उसके बिजनेस में नई जान आएगी।

नया मेन्यू कॉन्टिनेंटल और इंडियन डिशेज का कॉम्बिनेशन होगा। सबसे पहले इसे वीकेंड पर मुंबई में लॉन्च किया जाएगा। बाद में इसे समूचे भारत में पेश किया जाएगा। वेस्ट और साउथ इंडिया में मैकडॉनल्ड्स रेस्टोरेंट्स चलाने वाली वेस्टलाइफ डिवेलपमेंट के वाइस चेयरमैन अमित जटिया ने कहा, 'हम भारतीय व्यंजनों से प्रेरणा लेते रहते हैं और उन व्यंजनों को मैकडॉनल्ड के फॉर्मेट में पेश करते हैं। इनसे पश्चिमी जगत के फ्लेवर्स मिलते हैं, लेकिन भारतीयता की पहचान इनमें बनी रहती है।'

मैकडॉनल्ड्स के लिए ब्रेकफास्ट पर जोर देने की बात नई नहीं है। उदाहरण के लिए, इसके कुछ रेस्टोरेंट्स 2010 से ही सुबह जल्दी खुलते आ रहे हैं और अंडा, चीज और सॉसेज मफिन परोसते हैं। करीब दो दशक पहले मैकडॉनल्ड्स ने स्ट्रीट फूड से सबक लेकर आलू टिक्की बर्गर पेश किया था, जो इसके स्टोर्स में जोरदार ढंग से बिकने वाला प्रॉडक्ट बन गया।

मैकडॉनल्ड के अनुसार, हालांकि इस बार नई बात यह है कि एक अलग मेन्यू की पूरी रेंज ही पेश की जा रही है। मसाला डोसा बर्गर्स के अलावा कंपनी प्लेन और अंडा भुर्जी के अलावा हॉट केक्स भी बेचेगी। कंपनी ने कॉफी और हॉट बेवरेजेज के लिए इसी तरह की रणनीति बनाई थी, जब उसने मैककैफे को तीन साल पहले एक अलग फॉर्मेट में लॉन्च किया था। ताजा कदम भी कुछ हेल्दी ऑप्शंस पेश करने से जुड़ा है क्योंकि ज्यादातर व्यंजन फ्राइड नहीं, बल्कि ग्रिल्ड होंगे।

जटिया ने कहा, 'कामकाज पर निकलते हुए ब्रेकफास्ट करने का चलन बढ़ेगा। वेस्टर्न क्विक सर्विस रेस्टोरेंट के रूप में हम लोग इंडियन ब्रेकफास्ट मार्केट को नाटकीय रूप से बड़ा आकार देंगे।' उन्होंने कहा कि बाजार में काफी गुंजाइश है और जरूरी नहीं है कि मैकडॉनल्ड्स का मुकाबला उडुपी और ईरानी रेस्टोरेंट्स से होगा।

इंडिया में बाहर खाने-पीने के बाजार का आकार 94 अरब डॉलर यानी लगभग 5.85 लाख करोड़ रुपये का होने का अनुमान है, लेकिन इसका केवल 2 पर्सेंट हिस्सा संगठित क्षेत्र में है।

जनवरी के वैट आंकड़े बताएंगे नोटबंदी की हकीकत

नई दिल्ली। एजेंसी

केंद्र सरकार ने करीब दो दर्जन राज्यों के नवंबर और दिसंबर के वैट कलेक्शन के हवाले से व्यापार पर नोटबंदी के असर को खारिज करने की कोशिश जरूर की है, लेकिन वैट जानकारों की मानें तो यह आकलन जल्द ही कच्चा साबित होने जा रहा है। नवंबर में सभी राज्यों में एकसमान बंपर हाइक से पता चलता है कि पुराने नोट खपाने के लिए ट्रेडर्स ने वैध और अवैध, दोनों तरीकों से ज्यादा टैक्स चुकाया है। इसके अलावा दिसंबर और नवंबर में जमा होने वाला टैक्स क्रमशः नवंबर और अक्टूबर की बिक्री का है। ऐसे में 8 नवंबर से 31 दिसंबर के बीच व्यापार पर नोटबंदी के असर की हकीकत जनवरी के कलेक्शन से दिखनी शुरू होगी। दिल्ली वैट विभाग के एक सीनियर अधिकारी ने बताया, 'नवंबर में वैट 20 पर्सेंट बढ़ा था। उसके बाद दिसंबर में 4 पर्सेंट की गिरावट आ गई, लेकिन 1 से 10 जनवरी के बीच वैट कलेक्शन पिछले साल की इसी अवधि के मुकाबले करीब 8 पर्सेंट कम है। पूरे महीने का डेटा आने के बाद ही हम किसी ठोस नतीजे पर पहुंच सकते हैं।' दिल्ली के

वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया के एक एडवाइजर ने केंद्र के इस दावे पर सवाल उठाया कि 23 राज्यों के अलावा बाकी राज्यों ने अपना वैट डेटा मुहैया नहीं कराया था। उन्होंने कहा कि एक हफ्ते पहले ही खुद सिसोदिया ने जेटली से मिलकर चिंता जताई थी कि देश के वितरण केंद्र दिल्ली में वैट कलेक्शन नोटबंदी के बाद पहली बार नेगेटिव जोन में आ गया है।

आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि सभी राज्यों ने दिसंबर के अंत तक पुराने नोटों से वैट जमा कराने की छूट दे रखी थी। नवंबर में बहुत से व्यापारियों ने एडवांस टैक्स भरा, लेकिन एक तबके ने अपना काला धन खपाने के लिए बिक्री बढ़ा-चढ़ाकर दिखाई और ज्यादा से ज्यादा टैक्स भरा। यह ट्रेंड धीरे-धीरे मंद पड़ा, जो दिसंबर के कलेक्शन में साफ दिखता है।

सेल्स टैक्स बार एसोसिएशन के मेंबर और सीए पी के जैन ने बताया, 'वैट पीरियड साइकल 21 से 21 तारीख तक चलता है। 21 नवंबर तक जमा होने वाला टैक्स 31 अक्टूबर तक की बिक्री और 21 दिसंबर तक जमा होने वाला वैट 30 नवबंर तक की बिक्री को दर्शाता है। अगर 31 दिसंबर तक के कलेक्शन को भी शामिल करें तो भी उसमें ज्यादातर पिछले महीने के व्यापार का ही रुझान दिखेगा। 31 दिसंबर तक के व्यापार का टैक्स 21 जनवरी तक जमा होना है। ऐसे में जनवरी के आंकड़े नोटबंदी के बिक्री पर असर की सबसे सही तस्वीर पेश करेंगे और यह शुरुआत होगी।' दिल्ली जोन से केंद्र को जाने वाले एक्साइज, सर्विस और इनकम टैक्स में भी गिरावट आई है, जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में औद्योगिक सुस्ती की ओर से इशारा करता है।

बड़े सार्वजनिक उपक्रमों की निगाह ईपीएफओ के कोष पर

हैदराबाद। एजेंसी

देश के कई बड़े सार्वजनिक उपक्रम कर्मचारी भविष्य निधि संगठन :ईपीएफओः से कोष पाने की उम्मीद कर रहे हैं। ईपीएफओ के पास बड़ी मात्रा में नकदी है। श्रम मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने यह बात कही। मंत्री ने इस बात को स्वीकार किया कि नोटबंदी के बाद बैंक ब्याज दरों में गिरावट के मद्देनजर ईपीएफओ भी अपने निवेश पर बेहतर प्रतिफल की तलाश में है। दत्तात्रेय ने कहा कि बैंकों की ब्याज दर में कमी के बाद ईपीएफओ को भी अपने निवेश के तरीके की रणनीति में बदलाव करना पड़ रहा है ताकि इस कोष के अंशधारकों को बेहतर ब्याज दिया जा सके। ईपीएफओ ने हाल में इस साल के लिए 8.65 प्रतिशत की ब्याज दर की घोषणा की है। ईपीएफ अंशधारकों को 2014-15 में और 2015-16 में 8.80 प्रतिशत का ब्याज मिला था। दत्तात्रेय ने कहा कि फिलहाल ईपीएफओ अपने निवेश योग्य कोष का 20 प्रतिशत केंद्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों में निवेश कर सकता है। इस साल निवेश योग्य कोष करीब 1.3 लाख करोड़ रुपये है। मंत्रालय इसे बढ़ाकर 30 प्रतिशत करने पर विचार कर रहा है। दत्तात्रेय कहा, हम गंभीरता से इस पर विचार कर रहे हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के कई उपक्रमों को निवेश की जरूरत है। हम उनमें अधिक निवेश कर सकते हैं। भविष्य में हम अपनी प्राथमिकता बदल सकते हैं। हम केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों पर अधिक ध्यान देंगे।

इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज उद्घाटन

22 घंटे तक होगी ट्रेडिंग

गांधीनगर। एजेंसी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी (गिफ्ट) के इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर (आईएफएससी) में देश के पहले इंटरनेशनल एक्सचेंज 'इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज' (आईएनएक्स) का उद्घाटन किया।

इंडिया आईएनएक्स, बीएसई (बंबई स्टॉक एक्सचेंज) लिमिटेड के पूर्ण स्वामित्व वाली आनुषंगी कंपनी है। यह विश्व के सबसे आधुनिक प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म में से एक है और इसका टर्न अराउंड टाइम 4 माइक्रोसेकंड है। यहां 22 घंटे तक ट्रेडिंग होगी, जिससे अंतरराष्ट्रीय निवेशक एवं प्रवासी भारतीय विश्व में कहीं से भी भारत में ट्रेड कर सकें। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज का उद्घाटन भारत के वित्तीय क्षेत्र के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि प्रतिभा और प्रौद्योगिकी के संयोजन के साथ भारतीय कंपनियां विश्व के तमाम वित्तीय केंद्रों से प्रतियोगिता कर सकती हैं।

इस एक्सचेंज के जरिए भारतीय एक्सचेंज के साथ-साथ दुबई, लंदन, सिंगापुर जैसे विश्व के अन्य एक्सचेंज को कम दर पर विविध उत्पादों और प्रौद्योगिकी सेवाओं को उपलब्ध कराया जाएगा। इस अवसर पर बीएसई के चेयरमैन सुधाकर राव ने कहा, 'वित्तीय सेवाओं की दुनिया में बीएसई प्रणेता रही है और इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज की शुरुआत इसकी नवीनतम उपलब्धि है। हमें पूरा विश्वास है कि यह एक्सचेंज देश के बुनियादी ढांचे और विकास संबंधी जरूरतों के लिए पूंजी जुटाने

में महत्वपूर्ण योगदान देगा। यह समानांतर रूप से विश्व में टेक्नोलॉजी के स्तर पर बेहद एडवांस्ड प्लेटफॉर्म पर कम लेनदेन शुल्क के साथ सीमा पार निवेश के अवसर उपलब्ध कराएगा।'

आईएफएससी-गिफ्ट सिटी में स्थित यह एक्सचेंज टैक्स ढांचे और नियामकीय ढांचे के लिहाज से प्रतिस्पर्धात्मक तौर पर फायदेमंद है। इसमें प्रतिभूति लेनदेन कर, कमोडिटी (जिंस) लेनदेन कर, लाभांश वितरण कर और लंबी अवधि में पूंजीगत लाभ पर कर छूट के साथ ही आयकर से छूट जैसे लाभ शामिल हैं।

करीब 250 ट्रेडिंग सदस्य, जिनमें कमोडिटी और विदेशी ब्रोकर शामिल हैं, ने इंडिया आईएनएक्स के संग काम करने में दिलचस्पी दिखाई है। एक्सचेंज को उम्मीद है कि सभी प्रकार के प्रतिभागी एक ऐसी पारस्थितिकी विकसित करेंगे, जो इसे वैश्विक स्तर पर अन्य वित्तीय केंद्रों के मुकाबले ज्यादा प्रतिस्पर्धी बनाएगी।

'अल्टाबा' के नाम से जाना जाएगा याहू

न्यू यॉर्क। एजेंसी

मशहूर सर्च इंजन कंपनी याहू जिसकी अमेरिकी वायरलेस कम्यूनिकेशन सर्विस प्रवाइडर वेराइजन ने पिछले साल जुलाई में महज 4.8 अरब डॉलर में अधिग्रहण किया था, अब जल्द ही 'अल्टाबा' के नाम से जानी जाएगी। इसके साथ ही याहू के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मैरिसा मेयर के भी कंपनी के बोर्ड से इस्तीफा देने की खबर है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में बताया गया कि बिकने के बाद से याहू के छह निदेशक कंपनी छोड़कर जा चुके हैं, जिसमें मेयर भी शामिल हैं। वेराइजन ने याहू का अधिग्रहण डिजिटल विज्ञापन के क्षेत्र में अपने परिचालन को मजबूत करने के लिए किया है। विशेषज्ञों के मुताबिक वेराइजन के लिए याहू की संपत्तियों को एओएल से नहीं जोड़ना ठीक रहेगा, जिसका उसने 4.4 अरब डॉलर में अधिग्रहण किया है।

एओएल के पास द हफिंगटन पोस्ट और टेक्नॉलजी वेबसाइट टेकक्रंच और एनगैजट है और याहू के पास याहू फाइनेंस है। इस तरह से वेराइजन के पास अब मजबूत डिजिटल ऐडवर्टाइजिंग प्लैटफॉर्म हो गया है। वैश्विक मार्केट कंसल्टेंसी फर्म गार्टनर के शोध निदेशक विशाल त्रिपाठी ने बताया कि वेराइजन निश्चित रूप से याहू और एओएल दोनों कंपनियों के परिचालन को अपने हिसाब से बदलेगी ताकि इस सौदे का वह फायदा उठा सके। फोटो शेयरिंग वेबसाइट फ्लिकर और धीरे-धीरे लोकप्रियता हासिल कर रही माइक्रोब्लॉगिंग वेबसाइट टंबलर याहू की दो संपत्तियां है जिसमें विकास की काफी गुंजाइश है। त्रिपाठी ने कहा कि वेराइजन के पास अब टंबलर, फ्लिकर, याहू स्पोर्ट्स और याहू न्यूज है। इस तरह से वेराइजन के लिए यह सौदा काफी लाभकारी प्रतीत हो रहा है।

40 दिन में खुले 2 करोड़ नए अकाउंट, 3 लाख करोड़ हुआ डिपॉजिट

नई दिल्ली। एजेंसी

नोटबंदी के बाद के 40 दिनों में 2 करोड़ से अधिक नए बैंक खाते खुले और इनमें 3 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का डिपॉजिट हुआ। मोदी सरकार के इस कदम का यह बड़ा असर है। फाइनैंशल इंटेलिजेंस यूनिट (इफ्यू) के डेटा से पता चलता है कि पिछले साल 15 नवंबर से 25 दिसंबर के बीच 2.10 करोड़ नए बैंक खाते खुले और इनमें 3 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा रकम इनमें जमा की गई। इन खातों में जो रकम आई, उसमें से 50,000 करोड़ रुपये का कैश डिपॉजिट, जबकि 3 लाख करोड़ रुपये का नॉन-कैश डिपॉजिट (चेक और ड्राफ्ट के जरिये) आया।

इससे जुड़े अधिकारियों ने नोटबंदी पर सरकार के असेसमेंट की जानकारी दी। सरकार ने एफआईयू से यह डेटा इसलिए मांगा था ताकि नोटबंदी के असर को समझा जा सके। उन्होंने कहा कि बंद हुए नोटों का बड़ा हिस्सा अगर बैंकिंग सिस्टम में आया है तो यह स्कीम के फेल होने की निशानी नहीं है। सरकार टैक्स पेयर्स का दायरा बढ़ाना चाहती है और नोटबंदी से यह मकसद हासिल होता दिख रहा है। नोटबंदी से शुरू से जुड़े एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, 'जितना पैसा बैंकों में आया है, वह सामान्य हालत में पांच साल तक नहीं आता।' उन्होंने बताया कि जन धन योजना की शुरुआत के बाद दो साल में 20 करोड़ बैंक खाते खुले थे, लेकिन बिना किसी कोशिश के नोटबंदी के चलते महीने भर में तीन करोड़ नए खाते खुल गए। उन्होंने कहा कि बैंकों में जो पैसा आया है, उससे पता चलता है कि काले धन के जमाखोरों के पास दूसरा रास्ता नहीं बचा है। नोटबंदी के बाद उनके पास काले धन को खपाने के दो रास्ते थे। पहला तो वे इससे गोल्ड खरीदते। दूसरा उन्हें बैन किए गए नोटों को खत्म करना पड़ता।

उनके मुताबिक, सरकार को इसका भरोसा है कि कैशलेस पेमेंट की दिशा में एक बड़ा बदलाव लोगों में आ रहा है। एक अन्य अधिकारी ने बताया कि काले धन के रिस्क को लोग समझ रहे हैं। उन्होंने बताया कि गोल्ड में लोगों की दिलचस्पी कम करने और बैंक खातों की जांच के लिए नई नीतियों की योजना बन रही है। बैंक खातों की जांच से टैक्स चोरों को पकड़ने में मदद मिलेगी। टैक्स स्ट्रक्चर में बदलाव के बारे में भी सोचा जा रहा है। हालांकि, अधिकारियों ने बताया कि इनकम टैक्स रेट और टैक्स स्लैब में बदलाव इस पर निर्भर करेगा कि सरकार बजट से क्या मैसेज देना चाहती है। उन्होंने बताया कि टैक्स रेट को तर्कसंगत बनाने के साथ सरकार की तरफ से खर्च बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है।

किसानों के लिए राहत

शीत लहर से फलेगी गेहूं की फसल

नई दिल्ली । आईपीटी नेटवर्क

सरकार और लाखों किसानों के लिए यह राहत की बात साबित हो सकती है। भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) ने कहा है कि मंगलवार से शनिवार सुबह तक पंजाब, हरियाणा और उत्तरी राजस्थान में तेज शीत लहर की संभावना है। सामान्य की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक गर्म मौसम होने के कारण नमी की कमी झेल रही खेतों में खड़ी गेहूं और सरसों की फसल में शुक्रवार से उत्तरी भारत के अधिकांश भाग में हल्की बारिश होने से नई जान आ सकती है। पिछले महीने मौसम विभाग ने कहा था कि दिसंबर और फरवरी के बीच सभी उप-भागों में तापमान सामान्य से ज्यादा गरम रह सकता है।

असामान्य मौसम की वजह कृषि मंत्रालय में हाल ही में एक समीक्षा बैठक हुई थी। कहा जा रहा है कि इसमें जनवरी के आखिर तक प्रतीक्षा करने और हालात पर नजर रखने का निर्णय किया गया है। जनवरी के बाद गेहूं पकने के दौरान अगर तापमान बढ़ता है तो मुश्किल हो सकती है। मौटे तौर पर औसत तापमान में प्रति डिग्री सेल्सियस बढने से गेहूं की फसल में 10 प्रतिशत की गिरावट आ जाती है। भारत में गेहूं की फसल का औसत प्रति हेक्टेयर तीन से चार टन है और पंजाब में यह प्रति हेक्टेयर छह से सात टन है।

एक वरिष्ठ वैज्ञानिक ने कहा, 'कई स्थानों में गेहूं की फसल विकास के चरण में है और अगले 15-20 दिनों में लंबी गरम अवधि वास्तव में अंतिम फसल के लिए खराब हो जाएगी।' मौसम विभाग ने सोमवार को अपने पूर्वानुमान में कहा कि मंगलवार से शुक्रवार सुबह तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर भी सर्द लहर की स्थिति और पंजाब, हरियाणा तथा उत्तरी राजस्थान के क्षेत्रों में समान अवधि में पाला पडने की संभावना है। उत्तर के कई हिस्सों में हल्की बारिश हुई है जिससे तापमान आधे से एक डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है। पिछले हफ्ते तक यह अनुमान जताया गया है कि 3.031 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र में गेहूं की बुआई हुई है जो पिछले साल की समान अवधि से करीब 7.6 प्रतिशत ज्यादा है। हालांकि कई भागों में नकदी संकट को देखते हुए कई किसानों का कहना है कि उन्होंने पुराने बीजों का प्रयोग किया है। भारतीय मौसम विभाग के प्रमुख केजे रमेश ने पिछले महीने अखबार को बताया था कि देश भर का कुल तापमान सामान्य से ज्यादा रहेगा जबकि उत्तर भारत में शीत लहर की अवधि इस साल कम रहेगी।

पीओएस मशीन की खरीद पर कर में 16 प्रतिशत छूट देने का निर्णय

भोपाल। मध्यप्रदेश सरकार ने प्रदेश में नकदी रहित लेन देन को बढ़ावा देने के लिये प्वाइंट ऑफ सेल 'पीओएस' मशीन की खरीद पर वैट एवं प्रवेश कर से छूट देने का निर्णय लिया है। मध्यप्रदेश के वित्त मंत्री जयंत मलैया ने मंत्रिपरिषद के बैठक के बाद बताया, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रदेश में पीओएस मशीन को मध्यप्रदेश वैट अधिनियम 2002 के तहत 14 प्रतिशत वैट और दो प्रतिशत प्रवेश कर मिलाकर कुल 16 प्रतिशत कर से छूट देने की स्वीकृति दी गयी है। उन्होंने कहा कि सरकार ने यह कदम प्रदेश में नकदी रहित लेन देन को बढ़ावा देने के लिये उठाया है। उन्होंने बताया कि इसके अलावा मंत्रिपरिषद ने वित्तीय वर्ष 2016-17 में पारेषण प्रणाली सुदृढ़ीकरण की पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड की 354.78 करोड़ रुपये की राशि तथा तीनों विद्युत वितरण कंपनियों की वितरण प्रणाली सुदृढ़ीकरण के लिये 880.28 करोड़ रुपये की योजनाओं का अनुमोदन किया।

मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में 500 करोड़ रुपये के पूँजी निवेश से स्थापित होगा फूड पार्क

भोपाल। आईपीटी नेटवर्क

केंद्र सरकार ने मध्यप्रदेश के मंदसौर जिले की दलोदा तहसील में 500 करोड़ रुपये की लागत वाले मेगा फूड पार्क स्थापित करने की स्वीकृति दी है। प्रदेश के लिये यह एक अहम उपलब्धि है, जो किसानों की आय को दोगुना करने के लक्ष्य को पूरा करने में मददगार होगी। आधिकारिक तौर पर दी गयी जानकारी के अनुसार भारत सरकार के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने देश के 7 राज्यों में मेगा फूड पार्क को स्वीकृति प्रदान की है, जिनमें मध्यप्रदेश एक है।

इस फूड पार्क की स्थापना का काम मेसर्स चेतक इंटरप्राइजेस लिमिटेड कम्पनी द्वारा किया जायेगा। इसमें करीब 500 करोड़ रुपये का निवेश होगा। इस परियोजना में डाबर, झाण्डू, फार्मास्यूटिकल्स और पतंजलि जैसी बड़ी कम्पनियों को भी जोड़ा जायेगा। इस पार्क के स्थापित होने से मालवा अंचल के किसानों के साथ ही प्रदेश की सीमा से लगे राजस्थान के जिले के किसान भी लाभान्वित होंगे। मंदसौर जिले में कृषि फसलों के अलावा बड़ी मात्रा में उद्यानिकी, मसाला और औषधि बनाने में उपयोग होने वाली फसलों का उत्पादन भी होता है। फूलों की खेती भी यहाँ बड़े पैमाने पर होती है। फूड पार्क के स्थापित होने से इस पूरे क्षेत्र का औद्योगिक विकास होने के साथ ही रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।

जीएसटी सरल होगा, उद्योगों के लिए कम बोझवाला होगाः राजस्व सचिव

गांधीनगर। एजेंसी

केंद्रीय राजस्व सचिव हसमुख अधिया ने कहा कि प्रस्तावित नयी अप्रत्यक्ष कर प्रणाली वस्तु एवं सेवा कर :जीएटीः से कर व्यवस्था सरल और हल्के बोझ वाली होगी। इसमें केवल एक दर होगी और कर का भुगतान डेबिट:क्रेडिट कार्ड या चेक से किया जा सकेगा। अधिया ने यहां वाइब्रेंट गुजरात सम्मेलन में कहा कि व्यापारियों और उद्यामियों के लिए जीएसटी व्यवस्था में संसाधनों पर चुकाए गए कर को अपनी देनदारी में समायोजित कराना अधिक आसान होगा। इससे पूरे देश पर कर अनुपालन का बोझ हल्का होगा तथा पूरा देश एक साझा बाजार बन जाएगा। अधिया ने कहा, जीएसटी पर चलना बहुत ही आसान होगा। आप सबसे लिए यह बहुत ही सरल होगा। सीमाओं :राज्यों कीः कोई बाधा नहीं होगी और आप एक जगह से दूसरी जगह सामान आसानी से पहुंचा सकेंगे। तमाम छोटे छोटे कर खत्म हो जाएंगे । केवल एक एकीकृत कर लागू होगा। गौरतलब है कि सरकार ने 1 अप्रैल 2017 से जीएसटी लागू करने का लक्ष्य रखा है पर अधिकार सम्पन्न जीएसटी परिषद में राज्यों के साथ कुछ मसलों पर सहमति न बन पाने से यह समय सीमा मुश्किल लग रही है। इनमें करदाताओं की जांच के अधिकार का मसला भी शामिल है।

जीएसटी नियम आने के बाद अमल के लिए उद्योगों को चाहिए तीन महीने का समय

नयी दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

उद्योग जगत का मानना है कि वस्तु एवं सेवाकर :जीएसटीः में अंतिम सहमति बनने और नियम-कायदे जारी होने के बाद इस पर अमल के लिये उसे कम से कम तीन माह का समय चाहिये। देश के अग्रणी वाणिज्य एवं उद्योग मंडल फिक्की के नये अध्यक्ष पंकज आर. पटेल ने यह बात कही है।

उन्होंने कहा, हमें जीएसटी के रूल (नियम) चाहिये, एक बार नियम आ जायें तो उसके बाद हमें अपने सॉफ्टवेयर को उसके अनुरूप करने के लिये तीन माह का समय चाहिये।

पटेल ने कहा, मोटे तौर पर उद्योगों की सब तैयारी है, लेकिन किस वस्तु पर किस दर से कर लगेगा यह जीएसटी के नियम सामने आने के बाद ही पता चलेगा। हमारे आपूर्तिकर्ता

और आगे खरीदारों को भी नियमों के अनुरूप तैयारी करनी होगी। बिल बुक भी नई छपानी होगी, नियम आने पर ही यह तैयारी पूरी होगी। उल्लेखनीय है कि जीएसटी व्यवस्था को लागू करने के लिये जीएसटी परिषद ने चार स्तरीय कर ढांचे :पांच, 12, 18 और 28 प्रतिशतः को अंतिम रूप दिया है। इसमें आवश्यक वस्तुओं के लिये निचली दर होगी जबकि गैर-जरूरी और भोग विलास की वस्तुओं पर सबसे उंची दर से कर लगाया जायेगा।

सरकार का इरादा अगले वित्त वर्ष से जीएसटी लागू करने का है। वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता वाली जीएसटी परिषद अप्रत्यक्ष कर क्षेत्र की इस व्यवस्था को लागू करने के लिये तेजी से काम कर रही है। हालांकि, अभी कुछ मुद्दों पर केन्द्र और राज्यों के बीच सहमति नहीं बन पाई है जिसकी वजह से एक अप्रैल 2017 से जीएसटी लागू होना मुश्किल नजर आ रहा है।

स्वामी/मुद्रक/प्रकाशक सचिन बंसल द्वारा अपनी दुनिया प्रिंटर्स, 13, प्रेस काम्प्लेक्स, ए.बी. रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 18, सेक्टर-डी-2, सांवेर रोड, इंडस्ट्रीयल एरिया, जिला इंदौर (म.प्र.) से प्रकाशित । संपादक- सचिन बंसल

सूचना/चेतावनी- इंडियन प्लास्ट टाइम्स अखबार के पूरे या किसी भी भाग का उपयोग, पुनः प्रकाशन, या व्यावसायिक उपयोग बिना संपादक की अनुमति के करना वर्जित है। अखबार में छपे लेख या विज्ञापन का उद्देश्य सूचना और प्रस्तुतिकरण मात्र है। अखबार किसी भी प्रकार के लेख या विज्ञापन से किसी भी संस्थान की सिफारिश या समर्थन नहीं करता है। पाठक किसी भी व्यावसायिक गतिविधि के लिए स्वविवेक से निर्णय करें। किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र इंदौर, मप्र रहेगा।